

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

Jawai Dam Recharging Project for irrigation and drinking water purpose

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो आजादी से पहले बनना शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि उसके पुनर्भरण की योजना आज तक लागू नहीं की गई है। वह बांध 60 साल में मात्र 8 से 40 बार भरा है, इससे किसानों की जमीन भी प्यासी रहती है और गांव भी प्यासे रह जाते हैं। मूलतः वह पेयजल और irrigation दोनों के लिए काम आता है। इसमें दो बांध भी बनाए गए हैं, लेकिन पूरा पानी नहीं आने की वजह से पूरे 60 वर्षों में मात्र 8 से 10 बार भरा है और किसान अपनी खेती सिर्फ 8 से 10 बार कर पाया है। सरकार के मामले में यह पेंडिंग है। सरकार ने मंजूरी दी है और राजस्थान के लिए पांच योजनाएं तय की हैं, जिसमें जवाई बांध पुनर्भरण की भी योजना है। पाली, जालौर, सिरोही ये तीन जिले ऐसे हैं, जहां पीने के पानी की भी अव्यवस्था है और सिंचाई भी नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह एक गंभीर विषय है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप माननीय सरकार से यह निवेदन करें कि उस बांध की पुनर्भरण योजना तुरंत लागू की जाए।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to save farmers of Maharashtra from poisonous pesticides

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, the subject of my Zero Hour mention is "save Maharashtra farmers from poisonous pesticides". Sir, we are aware that pesticides have...

MR. CHAIRMAN: Please put the mask, Anilji and speak a little louder पूरा मास्क पहनकर, फिर थोड़ा लाउडर बोलिए।

SHRI ANIL DESAI: Sir, we are aware that use of pesticides enables farmers to produce more crops for a unit area with less tillage, reduce deforestation, help in conserving the natural resources and curbing soil erosion. Sir, pesticides are also critical for control of invasive species and noxious weeds. But, there are some pesticides which are not good and have harmful effects on the health of our Kisans. There are some brands which have deadly effects on the health of innocent farmers and farm labourers who spray pesticides in the fields. Sir, in recent years, several Kisans and farm labourers fell ill and unfortunately, about 63 of them have died, while spraying these pesticides in cotton, soyabean and other crops in Yavatmal and other Districts of Maharashtra. On receiving the complaints about the deaths of the farmers due to poisonous substances present in some branded pesticides, and also, in view of the fact that there is no antidote available for such pesticides, as concluded by the Special Expert Committee appointed by the Government of Maharashtra, some pesticides were notified and they were to be banned. According to the Nagpur Bench of Bombay High Court, the Government of Maharashtra took up this matter with the Central Government in March, 2018 and recommended for banning these deadly pesticides. Sir, the Central Government had issued a Notification on 14th May, 2020, banning 27 pesticides which were considered harmful including 'acephate' and 'monocrotophos' and recommended banning them by the State of Maharashtra. Sir, we welcome this step. But, at the same time, three of the deadly pesticides are yet to be banned. So, I would request the Government to look into the matter and ban those pesticides as early as possible to save the lives of the farmers.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

**Need to provide additional C.R.P.F. Battalions to the State of
Chhattisgarh to tackle naxal threat**

श्री पी.एल.पुनिया (उत्तर प्रदेश): सर, मैं छत्तीसगढ़ को आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को शीघ्र उपलब्ध कराने के बारे में कहना चाहता हूँ। वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सात अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियनें आवंटित की गई थी, जिनकी नक्सल विरोधी अभियानों में दक्षिण बस्तर के जिला सुकमा और बीजापुर में, अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक तैनाती नहीं हो सकी है। महोदय, चयनित लोकेशन पर बटालियन मुख्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु राशि आवंटित करके अधिकांश लोकेशन पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूरसंचार सुविधा में वृद्धि के लिए 525 मोबाइल टावर स्थापित किए जा चुके हैं। 1028 टावरों की स्वीकृति हेतु गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर से दस 10 सीआरपीएफ बटालियनों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के लिए 7 बटालियनों को उपलब्ध कराया जा सकता है। आपके माध्यम से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ को पूर्व से आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, जिससे नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

Need to resolve the issue of long pending dues of B.S.N.L. workers

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to deliver my Zero Hour submission. My topic today is about the BSNL Workers who are